शिक्षा में अभिनव कार्यक्रमों से प्राप्त सबक़ : लोक जुम्बिश - सभी की शिक्षा के लिए जन आन्दोलन[1]

शोभिता राजगोपाल



परिचय

राजस्थान राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार हुए हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली के भीतर समावेशन न करने की प्रथाओं और अन्तरालों को सम्बोधित करना है। इन नवाचारों से यह प्रमाणित होता है कि वंचित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ शैक्षिक योजना और उसे प्रदान करने के तरीक़ों में सुधार लाने के लिए सार्थक रणनीति विकसित की जा सकती है।

लोक जुम्बिश या पीपल्स मूवमेंट फ़ॉर एजुकेशन फ़ॉर ऑल को जून 1992 में भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (SIDA) के सहयोग से शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के मूल उद्देश्य से हुई थी। 1990 की परियोजना के दस्तावेज़ के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि 'मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित, निरूपित, उत्प्रेरित और बदला जाए ताकि हर बच्चे को बुनियादी शिक्षा (कक्षा I से VIII तक) मिल सके।'

लोक एक हिन्दी शब्द है जिसका अर्थ है 'लोग' और जुम्बिश एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ है 'हरकत'। दोनों शब्द मिलकर 'लोगों की हरकत' और 'लोगों के लिए हरकत' के विचार को व्यक्त करते हैं। लोक जुम्बिश ने यह प्रयास किया है कि शिक्षा के हर स्तर पर लोगों की सक्रिय और निरन्तर भागीदारी सुनिश्चित की जाए (चौधरी, 2003)।

लोक जुम्बिश समुदाय और शिक्षा सेवा प्रदाताओं को जुटाने, प्रेरित करने और सक्रिय करने के ध्येय के साथ शुरू हुई। यह परियोजना इस विश्वास पर आधारित थी कि जो राज्य प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्षरत था, वहाँ वर्तमान शिक्षा प्रणाली का कायाकल्प करने के लिए शिक्षा का सार्वभौमीकरण एक महत्त्वपूर्ण कारक है। इसलिए इसमें बच्चों की शिक्षा तक पहुँच, प्रतिधारण और उपलब्धि से सम्बन्धित मुद्दों की फिर से जाँच करने पर बल दिया गया है। परियोजना का पहला चरण 1992-1994 तक दो साल की अवधि के लिए था। इस चरण में लोक जुम्बिश ने 25 ब्लॉकों में काम किया। परियोजना के दूसरे चरण (1995-1998)[2] में, पहले चरण के दौरान प्राप्त उपलब्धियों को मज़बूत करने और समेकित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। 1999 के बाद लोक जुम्बिश को अनिश्चितता के दौर का सामना करना पड़ा और कार्यक्रम में धीरे-धीरे गिरावट आई तथा 2003 में कार्यक्रम समाप्त हो गया।

इस लेख में राजस्थान के विभिन्न ज़िलों में बच्चों को शिक्षा दिलाने के प्रयास में लोक जुम्बिश द्वारा अपनाए गए तरीक़ों और प्रमुख रणनीतियों की चर्चा की गई है। इसमें इस बात पर भी चर्चा की गई है कि इस हस्तक्षेप से कौन-कौन-सी प्रमुख बातें सीखने को मिलीं।

दृष्टिकोण

लोक जुम्बिश द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण एक गहन मिशन वाले तरीक़े के माध्यम से विकेन्द्रीकरण, सर्वसम्मति निर्माण व साझेदारी, भागीदारी योजना व मूल्यांकन और गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता के सिद्धान्तों पर आधारित था।

चूँकि लोक जुम्बिश एक प्रक्रिया संचालित परियोजना थी, इसलिए इस बात को लेकर एक स्पष्ट समझ थी कि इसके परिणाम सीधे क्षेत्र में की गई शुरुआत और वितरित की गई प्रक्रियाओं पर निर्भर होंगे। इसलिए प्रबन्धन की संरचना इस मान्यता पर आधारित थी कि वास्तविक समस्या केवल आपूर्ति की नहीं थी, बल्कि अप्रयुक्त क्षमताओं की भी थी और यह बात विद्यालय द्वारा की गई भागीदारी की निम्न दरों से स्पष्ट हुई।

परियोजना को लोक जुम्बिश परिषद के माध्यम से लागू किया गया था, जो एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय था और जिसे राज्य स्तर पर स्थापित किया गया था। लोक जुम्बिश कर्मियों और टीम को ध्यान से चुना गया था और उनमें शिक्षा विभाग के भीतर के व्यक्तियों को भी लिया गया था, जिनमें से कइयों को राजस्थान में महिला विकास परियोजना और शिक्षाकर्मी

[1]लेख के ड्राफ़्ट पर टिप्पणियाँ देने के लिए शोभा लोकनाथन कवूरी की आभारी हूँ।

[2]1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के मद्देनज़र SIDA ने परियोजना को दिया जाने वाला अपना समर्थन वापस ले लिया।

परियोजना जैसे अन्य अभिनव कार्यक्रमों में काम करने का अनुभव था। इसमें ऐसे व्यक्तियों को भी लिया गया जिन्हें विकास के क्षेत्र में काम करने का अच्छा अनुभव था।

एक प्रक्रिया-उन्मुख कार्यक्रम होने के नाते परिचालन की रणनीतियों में समुदाय की अधिकतम क्षमता पर ध्यान केन्द्रित किया गया। जिन क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया, उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं :

- शिक्षा का प्रबन्धन
- सामाजिक सहभाग
- शिक्षा की गुणवत्ता
- जेंडर समानता सुनिश्चित करना

शिक्षा का प्रबन्धन

लोक जुम्बिश के प्रबन्धन का सिद्धान्त काफ़ी गम्भीर था, जो एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली की ओर बदलाव का प्रतीक था। शिक्षा के प्रबन्धन के लिए निचले स्तर के प्रबन्धन वाली कई संरचनाएँ स्थापित की गई थीं। लोक जुम्बिश में विकेन्द्रीकृत योजना की इकाई गाँव और विकेन्द्रीकृत प्रबन्धन की इकाई विकास खण्ड था। एक संकुल/क्लस्टर बनाने के लिए 25-30 गाँवों को एक साथ जोड़ा गया। प्रत्येक विकास खण्ड को पाँच से सात सुसम्बद्ध संकुलों में विभाजित किया गया था। संकुल स्तर के कर्मचारियों की यह ज़िम्मेदारी थी कि वे ग्रामीण स्तर पर लोक जुम्बिश के लक्ष्यों को पूरा करें।

प्रारम्भ में पाँच विकास खण्डों की पहचान की गई थी, जिसमें एक ऐसी ऊर्ध्वगामी नियोजन प्रणाली बनाने का प्रयास किया गया जो समुदाय की विविध शैक्षिक आवश्यकताओं को सम्बोधित कर सके। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप प्रेरक दल (कोर टीम जिसमें एक तिहाई से आधी संख्या महिला सदस्यों की थी) बनाया गया, भवन निर्माण समिति का गठन हुआ और फिर जुटाव और शैक्षिक सहायता के लिए ग्राम शिक्षा समितियों (VECs) और संकुल स्तर के समूहों की शुरुआत हुई। विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड स्तरीय शिक्षा प्रबन्धन समिति ने सहायता प्रदान की और परियोजना की निगरानी की। राज्य स्तर पर अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति ने तिमाही आधार पर प्रगति की समीक्षा की (रामचन्द्रन, 2016)।

गोविन्दा (1997) का कहना है कि ‘लोक जुम्बिश की प्रबन्धन प्रणाली केन्द्रीकृत, पदानुक्रमित ढंग से कार्य करने के तरीक़े की विरोधी थी।’ शैक्षिक योजना न केवल विकेन्द्रीकृत थी, बल्कि यह एक ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया भी थी। ज़मीनी स्तर पर हुए अनुभवों ने लोक जुम्बिश के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और/या संशोधन में मदद की।

सामुदायिक जुटाव

लोक जुम्बिश का एक प्रमुख पहलू शिक्षा के लिए समुदाय को जुटाना और एक ऐसा वातावरण तैयार करना था जहाँ माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए खुद भी प्रेरित हों। परियोजना के दस्तावेज़ में काम करने वाले बच्चों, औपचारिक स्कूलों में न जा सकने वाली बालिकाओं, प्रवासी/ख़ानाबदोश परिवारों के बच्चों, आदिवासी बच्चों और विकलांग बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। जो बच्चे मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए थे, उनको सक्षम बनाने पर भी ज़ोर दिया गया।

समुदायों को जुटाने का प्रयास करने के लिए कुछ प्रमुख रणनीतियाँ विकसित की गईं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

शाला मानचित्रण और माइक्रो-प्लानिंग

लोक जुम्बिश ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए केन्द्रीकृत योजना की ऐसी कुछ कमियों पर काबू पाने के एक प्रभावी साधन के रूप में शाला मानचित्रण को चुना जिनकी वज़ह से राजस्थान में सार्वभौमिक पहुँच और भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई थी (गोविन्दा, 1998)।

शाला मानचित्रण एक महत्त्वपूर्ण साधन था। इसका उपयोग सामाजिक जुटाव के लिए और समुदाय को अपने गाँवों में शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण करने और प्राथमिक स्कूली शिक्षा के लिए बच्चों की पहुँच की योजना बनाने में शामिल करने के लिए किया जाता था। इस प्रक्रिया से क्षेत्र में बच्चों के लिए उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का व्यापक मूल्यांकन किया जा सका। इस अभ्यास के दौरान गाँव के प्रत्येक घर को एक मानचित्र पर दृष्टिगत रूप से चित्रित किया गया था। स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चों और उनके नामांकन की स्थिति का विवरण एकत्र किया गया और उसका मानचित्रण किया गया। स्कूलों की अवस्थिति और मौजूदा सुविधाओं को भी मानचित्र पर दर्शाया गया था।

शाला मानचित्रण की गतिविधियों जैसे सर्वेक्षण, स्कूल का नक़्शा और स्कूल सुधार कार्यक्रमों की तैयारी में शामिल होने से समुदाय के सदस्यों की भागीदारी को सुदृढ़ करने में मदद मिली। सामूहिक विश्लेषण से समुदाय को गाँव में मौजूदा शैक्षिक स्थिति को समझने में मदद मिली। शाला मानचित्रण में बालिकाओं की स्थिति को समझने के लिए प्रमुख रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया था। प्रारम्भ में तो बालिकाओं की बेहद कम संख्या की सूचना मिली थी; तब यह निर्णय लिया गया कि ‘अनदेखी’ और ‘छिपाई गई’ बालिकाओं की तलाश के लिए एक सचेत प्रयास किया जाए।

लोक जुम्बिश कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध

था कि बस्ती के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो, इसलिए स्कूल और ग़ैर-औपचारिक केन्द्रों में बच्चों की नियमित भागीदारी की योजना बनाने और उसे सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो-प्लानिंग (सूक्ष्म नियोजन) की गई। आमतौर पर गाँव में आवश्यक शैक्षिक अवसंरचना उपलब्ध कराने के बाद माइक्रो-प्लानिंग शुरू की जाती थी। लोक जुम्बिश में माइक्रो-प्लानिंग परिवार-वार थी, जबकि मूल रूप से ग्राम शिक्षा समितियों (VEC) के सदस्यों और ग्राम समुदाय की मदद से लोक जुम्बिश के संकुल कर्मियों द्वारा बच्चा-वार योजना और निगरानी की गई। ग्राम शिक्षा समितियों ने गैर-नामांकित बच्चों की पहचान की, सम्बन्धित परिवारों से सम्पर्क किया और स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और स्कूल में रुकने की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियाँ शुरू कीं।

माइक्रो-प्लानिंग के दो साधन, जो धीरे-धीरे प्राथमिक शिक्षा के प्रभावी सार्वभौमीकरण के साधन बन गए, इस प्रकार हैं :

(i) ग्राम शिक्षा रजिस्टर (ii) प्रत्येक स्कूल और ग़ैर-औपचारिक शिक्षण केन्द्र द्वारा बनाया गया प्रतिधारण/रिटेंशन रजिस्टर।

माइक्रो-प्लानिंग पर ज़ोर देने के कारण विभिन्न विकास खण्डों में विभिन्न पहलें हुईं जैसे प्रवासी परिवारों के बच्चों के लिए कम लागत वाले छात्रावास की योजना बनाना, बीकानेर के लूणकरणसर में बालिकाओं के लिए बालशिविरों व आवासीय शिविरों की स्थापना और भरतपुर के कामां में मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्चों को सुविधाएँ प्रदान करना (राजगोपाल, 2003)।

शिक्षा की गुणवत्ता

शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए शिक्षकों और शिक्षक-शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि उस समय शुरू किए गए न्यूनतम अधिगम स्तर (एमएलएल) के आधार पर एक पाठ्यक्रम और शैक्षणिक पैकेज के सुधारों को आरम्भ करने और उन्हें बढ़ावा देने में मदद मिल सके।

न्यूनतम अधिगम स्तर

लोक जुम्बिश ने प्रत्येक चरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 द्वारा निर्धारित अधिगम के न्यूनतम स्तर को हासिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। तेरह पाठ्यपुस्तकों सहित कार्यपुस्तिकाओं को विकसित किया गया और उन्हें कक्षा 1 से 5 में उपयोग में लाया गया। पूरक शिक्षण-अधिगम सामग्री भी विकसित की गई और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। एमएलएल आधारित पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण विधियों को पहले 1992 में केवल 45 स्कूलों में शुरू किया गया।

शिक्षक प्रशिक्षण

लोक जुम्बिश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मुद्दों को सम्बोधित करने के लिए शिक्षक-प्रशिक्षण एक महत्त्वपूर्ण रणनीति थी। शिक्षक की सकारात्मक सामाजिक छवि बनाने और निरन्तर प्रशिक्षण देने पर ज़ोर दिया गया। प्रशिक्षण से पहले शिक्षकों के साथ एक संवाद शुरू किया गया। प्रशिक्षण में शिक्षकों को प्रेरित करने और संवेदनशील बनाने के साथ-साथ उनके शैक्षणिक कौशल को तेज़ करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। एमएलएल पर क्षमता आधारित प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए थे। इन प्रशिक्षणों में सन्धान प्रशिक्षण और अनुसन्धान संस्था[3] की भूमिका प्रमुख थी।

सहज शिक्षा केन्द्र (ग़ैर-औपचारिक शिक्षण केन्द्र)

मुख्यधारा की शिक्षा से वंचित रह गए बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहज शिक्षा केन्द्रों (एसएसके) की स्थापना की गई। एसएसके पहल इस बात पर आधारित थी कि शिक्षा और काम के बीच परस्पर विरोधी प्राथमिकताएँ तभी हल हो सकती हैं जब कुछ यथार्थवादी विकल्प उपलब्ध हों। एसएसके को शुरू में सरकार द्वारा संचालित एनएफई केन्द्रों की तर्ज पर डिज़ाइन किया गया था। बाद में इन केन्द्रों का ध्यान ऐसी शिक्षा प्रदान करने पर था जो प्रासंगिक और आसानी से अनुकूलनशील हो तथा समग्र और रचनात्मक अधिगम को बढ़ावा दे।

शिक्षा बच्चों के दैनिक जीवन से सम्बन्धित थी। एसएसके में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में अधिक निवेश और बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण में बहु-कक्षीय शिक्षण के सन्दर्भ में विषय सम्बन्धी ज्ञान और शैक्षणिक कौशल बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। बाल केन्द्रित दृष्टिकोण, समय में लचीलापन, बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से पाठ्यक्रम का अनुकूलन और उनके अनुभव को नए ज्ञान के साथ जोड़ने में समुदाय की व्यापक भागीदारी ने बड़ी संख्या में बच्चों, ख़ासकर बालिकाओं को सन्दर्भ के अनुरूप संगत शिक्षा प्रदान करने में मदद की (राजगोपाल, 2003)।

साम्यता सुनिश्चित करना

शैक्षिक पहुँच और परिणामों में जेंडर समानता सुनिश्चित करना लोक जुम्बिश की प्राथमिकता थी। इस बात को लेकर एक स्पष्ट मान्यता थी कि जब तक जेंडर समानता, महिलाओं की गरिमा और स्थिति के मुद्दों को सम्बोधित नहीं किया जाता

[3] सन्धान शोध और प्रशिक्षण की एक एजेंसी थी जिसे मूलभूत रूप से लोक जुम्बिश में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शामिल किया गया था।

तब तक समान शिक्षा की ओर बढ़ना सम्भव नहीं है। प्रमुख रणनीतियों में निम्नलिखित बातें शामिल थीं :

महिला समूहों को बढ़ावा देना

ग्रामीण स्तर पर गठित महिला समूहों ने महिलाओं की इस बात में मदद की कि वे गम्भीर रूप से समाज में महिलाओं की अवस्था और स्थिति का विश्लेषण कर सकें और उसे शैक्षिक अवसरों और अभाव के मुद्दों से जोड़ सकें। ऐसे कई उदाहरण थे जहाँ महिला-समूहों की सदस्याओं ने स्कूलों के कामकाज और शिक्षक की उपस्थिति पर सख़्त नज़र रखी।

अध्यापिका मंच

एमएलएल प्रशिक्षणों में अध्यापिकाओं की कम भागीदारी ने अध्यापिका मंच का निर्माण किया, जहाँ अध्यापिकाओं ने अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं पर चर्चा की। अध्यापिकाओं को ये मंच अलगाव से बाहर आने और सशक्त महसूस करने का एक प्रभावी माध्यम लगे। ये मंच अध्यापिकाओं की आत्म-छवि बनाने का एक महत्त्वपूर्ण साधन बन गए और इसके परिणामस्वरूप गाँवों में महिलाओं के समूहों की आत्म-छवि भी विकसित हुई।

संवादिका

महिलाओं के विकास से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक और मंच की स्थापना की गई जिसे संवादिका कहा गया। इस मंच की कार्यसूची में से एक कार्य यह था कि जेंडर की दृष्टि से सभी क्षेत्र स्तर की गतिविधियों की समीक्षा की जाए।

बालिका शिक्षण शिविर

बालिका शिक्षण शिविर स्कूल न जाने वाली बालिकाओं के लिए शुरू किए गए थे, जो स्कूली शिक्षा के अवसर से चूक गई थीं। इसने बालिकाओं को मुख्यधारा की स्कूली शिक्षा में फिर से प्रवेश दिलाने के लिए एक पुल बनाने के कार्यक्रम के रूप में कार्य किया। राज्य के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश को देखते हुए इन आवासीय शिविरों में बालिकाओं को भेजने के लिए माता-पिता को समझाना और उन्हें इन शिविरों में बनाए रखना एक साहसिक क़दम था।

लोक जुम्बिश से प्राप्त सबक़

लोक जुम्बिश परियोजना को राजस्थान में सार्वभौमिक शिक्षा के स्पष्ट इरादे के साथ लागू किया गया था। एकल बिन्दु प्रविष्टि के विपरीत इस परियोजना का उद्देश्य कई स्तरों पर मुद्दों को सम्बोधित करना था। एक विकास खण्ड के सभी औपचारिक और ग़ैर-औपचारिक शिक्षण केन्द्र इस हस्तक्षेप के दायरे में आए।

विकेन्द्रीकृत स्थानीय स्तर की योजना और निर्णय लेने में लचीलेपन ने बड़ी संख्या में बच्चों को शैक्षिक धारा तक पहुँचने में सक्षम बनाया। इसके अलावा जेंडर को प्रमुखता देने वाली बात ने विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त संस्थागत प्रणाली को स्थापित करने का नेतृत्व किया।

परियोजना ने शैक्षिक प्रक्रियाओं के स्थानीय स्तर के प्रबन्धन को लागू करके समुदाय और शैक्षिक वितरण प्रणाली के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की। शिक्षा की आपूर्ति और माँग दोनों पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करने से यह स्थापित करने में भी मदद मिली कि किसी भी शैक्षिक प्रयास को टुकड़ों में करने की बजाय निरन्तरता के साथ करना चाहिए।

इस परियोजना ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की दिशा में काम किया और ऐसा करने के लिए सरकारी एजेंसियों, शिक्षकों, ग़ैर-सरकारी संगठनों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और समुदायों को सहभागी बनाया तथा एक समूह के रूप में सबके साथ मिलकर कार्य किया।

निष्कर्ष

हालाँकि लोक जुम्बिश 2003 के बाद समाप्त हो गया लेकिन इसने बच्चों को शिक्षा देने के विचार की गति बढ़ाई और यह कार्यक्रम उन बच्चों तक पहुँचा जो मुख्यधारा की शिक्षा से बाहर रखे गए थे। यह एक ऐसी पहल थी जो धीरे-धीरे विकसित हुई और जिसने समुदाय-आधारित प्रक्रियाओं के माध्यम से शिक्षा मुहैया कराने से सम्बन्धित दीर्घकालिक मुद्दों को सम्बोधित किया।

References:

1 Chaudhary, S.(2000) *Universal Elementary Education in Rajasthan, A study with focus on Innovative Strategies*, MHRD, GoI and NIEPA, New Delhi

2. Govinda, R.(1998) 'Reaching the Unreached through Participatory Planning'-Study of School Mapping in LokJumbish, IIEP, Paris and NIEPA, New Delhi sourced http//: www.unesco.org/iiep

3. .....(1997) LokJumbish: An Innovation in Grassroots level Management of Primary education, UNICEF, New York Sourced unesdoc.unesco.org

4. Rajagopal, S .(2003) 'Operationalising the Right to Education: The LokJumbish Experience in Rajasthan: N.Kabeer, G.B Nambissan and R. Subramanian (eds) *Child Labour and Right to Education in South Asia, Needs versus Rights*, Sage, New Delhi

5. Ramachandran, V.(2016) 'Legacy of Three Innovative Programmes' in Singh, A.K (ed) *Education and Empowerment in India*: Policies and Practices, Routledge, South Asia Edition , New Delhi

---

शोभिता राजगोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ़ डेवलपमेंट स्टडीज़, जयपुर में एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं। उन्हें जेंडर सम्बन्धी दृष्टिकोण को मुख्यधारा में लाने, महिलाओं के अधिकार व सशक्तिकरण और जेंडर व शिक्षा तथा प्रजनन स्वास्थ्य से सम्बन्धित मुद्दों पर शोध, नीति पक्ष समर्थन और प्रशिक्षण का व्यापक अनुभव है। इन मुद्दों पर उनके कई राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। वे राजस्थान और भारत के महिला-आन्दोलनों, ग़ैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के आन्दोलनों में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं। उनसे *shobhita@idsj.org* पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद :** नलिनी रावल